Reduction in the impetus to personalised modes of transport

926. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has recommended to Government to reverse the trend of giving unprecedented impetus to personalised modes of transport in the country; and

(b) if so, what decision has been taken by Government on the recommendations of the Commission?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The Seventh Five Year Plan document, Vol. II, in Para 8.14, mentions that the Public Transport System is required to be strengthened being much more energy efficient than personalised motor transport, and that the efforts would be made to introduce electricity-based mass transit systems in major cities. Referring to this, the Planning Commission in its Mid-Term Appraisal of the 7th Plan, have noted that, in actuality, the personalised modes of transports have received an unprecedented impetus and that, to reverse the trend, the public transport systems, both for intercity public transport systems, both for intercity and intra-city traffic, should be beefed up.

Efforts have been made during the 7th Five Year Plan period to strengthen the fleet-strength of State Transport Undertakings, who are the major providers of the bus transport in the country. Their total fleet strength which stood at about 80,000 buses in 1984-85 (last year of the 6th Plan) has grown to about 92,000 in 1987-88, recording an increase of about 15%.

साक्षरता संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत आदिवासियों के लिए साक्षरता

927. **श्री अजीत जोगी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि साक्षरता संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन ने आदिवासी क्षेत्रों में अत्यन्त अल्प साक्षरता के बावजूद आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए ऐसी कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की है जिससे उनकी साक्षरता की दर को मैदानी इलाकों के बराबर लाया जा सके?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. साहो) : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 15.35 आय वर्ग के 8 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, 1990 तक 3 करोड़ व्यक्तियों को तथा अतिरिक्त 5 करोड़ को 1995 तक । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष रूप से महिलाओं तथा अनुसूचित *जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों* पर ध्यान दिया जाएगा ।

अनुसूचित जनजाति को अधिक रूप से शामिल करने के लिए पहले ही किये गये विशिष्ट उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) उन सभी जिलों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है ।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रौढ़-शिक्षा में नामांकित शिक्षुओं में से कम से कम 50 % महिलायें तथा 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से हों ।

(iii) सभी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों तथा राज्य संसाधन केन्द्रों से अनुरोध किया गया है कि अधिकांश वर्गों द्वारा बोली जाने वाली भाषा (भाषाओं) में, जो क्षेत्रीय भाषाओं से अलग हों, शिक्षण, अध्ययन सामग्री विकसित की जाए ।

(iv) जहां तक संभव हो अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने को प्राथमिकता दी जाए ।

(v) जन शिक्षण निलायम की योजना के अन्तर्गत प्रेरक की नियुक्ति उन व्यक्तियों से की जाएगी, जिन्होंने समुदाय विशेषकर महिलाओं और समाज में आर्थिक रूप से अभावग्रस्त लोगों की सेवा करने में रुचि दिखाई है । महिलाओं और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्बन्ध में